

THE  
PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT IN

THE SEVENTY-FIRST SESSION OF THE RAJYA SABHA

*Commencing on the 20th February, 1970/ the 1st Phalgun, 1891  
(Saka)*

**RAJYA SABHA**

*Friday, the 20th February, 1970/Ae 1st  
Phalgun, 1891 (.Saka)*

The House met at forty minutes past twelve of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

**PRESIDENT'S ADDRESS MR.**

**CHAIRMAN : Secretary.**

SECRETARY, Sir, I beg to lay on the Table...

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, I rise on a point of order. Sir, the convention is that the President addresses the Members of Parliament, of both the Houses, in the Central Hall in a Joint Session. He reads the English version himself and makes the Vice-President read the Hindi version. But today the English version was read by the President of India and the Hindi translation was given to the Members by a stranger. That has never been the convention, Sir. Therefore to maintain the dignity of the House I think the House does not take cognisance of the President's Address given in Hindi. If at all, only the English version of the President's Address can be laid on the Table of the House, because a stranger can never address the Members of Parliament, of both the Houses. The staff of the President is not the President or the Vice-President; he is only a stranger. It is very unconventional and really derogatory to the Members of both the Houses that the staff has been asked to read out the Hindi version. I want your ruling on this point. SHRI R. S. DOOGAR (West Bengal) : Sir, this is a matter which really needs consideration.

**श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) :** श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर थोड़ा सा इनसे भिन्न

है। हमारा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि राष्ट्रपति का सम्बोधन इंगलिश और हिन्दी दोनों में रखा जाता है और अभी तक जैसी परम्परा थी, जैसा कि सम्मानित सदस्यों ने बताया, वह ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति इंगलिश पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति हिन्दी पढ़ते हैं और राष्ट्रपति हिन्दी पढ़ते हैं तो उपराष्ट्रपति इंगलिश पढ़ते हैं, यह परम्परा रही है, मगर आज राष्ट्रपति के सेक्रेटरी ने हिन्दी अनुवाद पढ़ा तो वह सेक्रेटरी का सम्बोधन तो हो सकता है मगर राष्ट्रपति का सम्बोधन नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति सन्निहित है मगर सेक्रेटरी में राष्ट्रपति सन्निहित नहीं है। जरा सुन लीजिये। इसलिये सेक्रेटरी द्वारा पढ़ा गया एड्रेस वह सेक्रेटरी का एड्रेस माना जायगा, वह राष्ट्रपति का एड्रेस माना ही नहीं जा सकता। उपराष्ट्रपति पढ़ते तो वह अवश्य ही राष्ट्रपति का एड्रेस माना जा सकता था और माना जाता रहा है। लेकिन चूँकि दोनों भाषाओं में एड्रेस होता है तो मैं माननीय सदस्य की इस राय से सहमत नहीं हूँ कि अंग्रेजी वर्जन तो माना जाय और हिन्दी वर्जन न माना जाय क्योंकि जब तक दोनों में न हो, अंग्रेजी और हिन्दी में न हो, तब तक एक भी न माना जाय और क्योंकि हिन्दी का सेक्रेटरी का सम्बोधन हो गया, अंग्रेजी का प्रेसिडेंट का सम्बोधन हो गया, और अब हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के सम्बोधन होने हैं इसलिये अब दो सम्बोधन ये हो नहीं सकते। एक ही सम्बोधन हो सकेगा, इसलिये यहां न हिन्दी का रखा जा सकता है न अंग्रेजी का रखा जा सकता है जब तक कि दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा न पढ़ा जाय।

**[श्री राजनारायण]**

श्रीमन्, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, मैंने राष्ट्रपति महोदय को 9 बजे, साढ़े 9 बजे, एक खत भेजा, राष्ट्रपति महोदय को अपील की, और उसकी एक कापी यहाँ भी है, श्रीमन्, उसको मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ, आज राष्ट्रपति का राष्ट्रपतित्व प्रधान मंत्री के प्रधान मंत्रित्व में समाविष्ट कर गया है, इसलिये मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ. . .

**श्री सभापति :** आप कह चुके ।

**श्री राजनारायण :** . . . कि राष्ट्रपति अपनी तमाम राष्ट्रपति की महिमा, गरिमा और तमाम शोभा को बिगाड़ चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने केरल में किया, जिस तरह से उन्होंने मनीपुर में किया, जिस तरह से उन्होंने बिहार में किया, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, यह राष्ट्रपति के काले कारनामे हैं । . .

**कई माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं ।

**श्री राजनारायण :** . . . इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का भाषण तो यह माना ही नहीं जा सकता, इसलिये आज सदन की मेज पर आपके सेक्रेटरी द्वारा राष्ट्रपति के भाषण को हार्गिज हार्गिज रखा नहीं जा सकता और उसको राष्ट्रपति का भाषण मानने के लिये हम लोग कतई तैयार नहीं होंगे, इसलिये इस पर पूरी व्यवस्था होनी चाहिये और तब इसके बाद कोई भाषण यहाँ पर होना चाहिये ।

**श्री सभापति :** बस कीजिये ।

**श्री राजनारायण :** सुनिये, श्रीमन् ! आप यहाँ विराजमान हैं, मैं जानता हूँ कि आपकी हिन्दी अच्छी है । . . .

**श्री सी० डी० पांडे (उत्तर प्रदेश) :** बहुत अच्छी है ।

**श्री राजनारायण :** . . . आपकी अभिव्यक्ति भी अच्छी है, आप अच्छी हिन्दी जानते हैं, आपके भाषण की कला भी अच्छी है, मगर एक सेक्रेटरी आ कर के राष्ट्रपति का भाषण

पढ़े और उसको सेक्रेटरी का भाषण हम मानें और यहाँ इस सदन के जो सचिव हैं, राज्य सभा के माननीय सचिव हैं, बनर्जी साहब—राष्ट्रपति के सेक्रेटरी ने यह पढ़ दिया—यह राज्य सभा के सेक्रेटरी है यह राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के सेक्रेटरी नहीं हैं कि राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के भाषण को हमारे सम्मानित सेक्रेटरी ले करें और कहें कि यह राष्ट्रपति का सम्बोधन है और उसको मैं ले करता हूँ । प्रत्येक सभ्य जनतंत्री और संसदीय और संवैधानिक मान्यताओं के विरुद्ध यह काम हुआ है । राष्ट्रपति महोदय की इसके लिये निन्दा होनी चाहिये । क्यों उन्होंने अपने साथ वहाँ पर सेक्रेटरी को आने की आज्ञा प्रदान की. . .

**श्री सभापति :** अच्छा हो गया ।

**श्री राजनारायण :** . . . क्यों नहीं उन्होंने आपसे कहा कि आप उसको पढ़ें । इसलिये इन बातों पर सोच विचार कर के अपनी व्यवस्था दें ।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, I have a submission to make. The point that has been made should certainly be considered. But personally I was under the impression that because there was no simultaneous translation arrangement, it was only a translation which was being made. I thought he was doing it standing nearby. But the point that has been made is to be considered. As a Member sitting there I took it as a translation; only it was not being done from a cubicle; it was being done by somebody standing by him. As a translation it is all right but as an Address it is not. In that situation, Sir, if you do not mind, I am very agreeable to making a suggestion that there may be a joint Session again and a new Address. (Interruptions) What is there? I do not want to put them in the wrong, but if you pass on this message, we can have a little tea break and hear you, Sir.

Another point which I want to bring to your notice is that your office has circulated a bulletin regarding the arrest of Shri Chandra Shekhar.

MR. CHAIRMAN : That is another matter.

(Interruptions)

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : That cannot be raised at this stage. Unless this point is over, we cannot take it up. That is my submission.

(Interruptions).

श्री राजनारायण : केवल राष्ट्रपति के सम्बोधन पर ही हमें अपने को सीमित रखना है। हमारे सम्मानित सदस्य श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी की गुलामी में कितने रत हैं कि उनके गुट का जहां भी नाम आया तब वह खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ लेकिन अगली जिस चीज को वह ले रहे हैं उसको न लें।

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

श्री श्रवणेश्वर प्रसाद सिंह (बिहार) : अगर राजनारायण जी कुछ और कोई बात उठा सकते थे तो भूपेश गुप्ता को भी हक है। वह हक क्यों छीना जाता है। बोलिये आप जिस पर आपको कहना था, आप चन्द्र शेखर जी के बारे में बोल रहे हैं।

MR. CHAIRMAN : No, no. Shri B.K.P. Sinha.

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar) : Mr. Chairman, I have listened carefully to the objections regarding the Address of the President and the Hindi translation of it. It appears to me that this is hair-splitting of a type which would not be permissible even in the courts of law which are the forums for hair-splitting. This year the President, in my opinion, has adopted a procedure which is an improvement on the past procedure. He used to read his speech from A to Z in English and the Hindi-knowing Vice-President or some other person read it in Hindi. This year he has introduced a new procedure to save time. An authorised version of the translation was being read out by his Secretary. If the contention of the hon. Members is correct that what has been read by the Secretary cannot be treated as authorised, then all international communications will become impossible. Suppose Mr. Khrushchev comes here, it is some other Russian who translates or interprets his speeches. Even in international con-

ferences there are interpreters and if their interpretation is not treated as authentic, then no international conference can be held and there will be no agreement at all. Therefore I do not see much of a point in what the hon. Members have said. Both the versions in my opinion, can be laid on the Table of the House.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Sir, I rise to oppose the point of order raised by my friend, Shrimati Yashoda Reddy. It seems that the memory of the hon. Member is too short. When the President assumed his office, he made a speech and the Hindi version of that speech was read out by the Secretary to the President, Dr. Nagendra Singh, the same gentleman who has read the Hindi version to-day, and, if may say so, that was a more solemn occasion than the joint address to the Members of Parliament because that was the occasion when the President was assuming charge and when he was becoming Rashtrapati for the first time. So, I oppose the point of order because what we have accepted as an accomplished fact we cannot question to-day.

THE LEADER OF THE OPPOSITION

श्री राजनारायण : देखिये एक मिनट हमें सुन लिया जाय। मेरा जो पाइन्ट है, मेरे पाइन्ट को श्रीमन् न तो भूपेश गुप्त ने कहा, मेरे पाइन्ट को न तो भार्गव जी ने कहा...

MR CHAIRMAN : Please sit down. I will not allow you.

श्री राजनारायण : ...और न मेरे पाइन्ट को, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ श्री बी० के० पी० सिंह, उन्होंने भी कहा...

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

श्री राजनारायण : यह जाइन्ट सेशन की बात है।

(SHRI S. N. MISHRA) : Mr. Chairman, it is with great reluctance that I have to add my voice to the point of order which has been raised before the House. I am in favour of it. It is because I consider it my duty to protect the dignity of the House. This is definitely a disrespect to our House and also both the Houses—and a gross violation of the rules and conventions in

[Shri S. N. Mishra] this regard. May I say that there had been earlier a serious lapse on the part of the Government but that did not relate to a matter of substance like the President's Address. In 1967 hon. Members would refresh their memory, there was the version of the National Anthem being sung at that time and nobody seems to have been held responsible for it. Everybody seems to be getting away with any kind of lapse that can happen in such august bodies. To-day there has been a serious lapse and a stranger has addressed us and a stranger can, by no manner of description, be said to be identified, and cannot be identified in any manner, with the President. It is the President whom we have the privilege to hear on this particular occasion, or the Vice-President if the President is pleased to ask the Vice-President to deliver the Address. A submission is made to you that the speech here can be interpreted as a translation by the Secretary. I must say that I would like to differ from that, not in this House, within the four corners of this House. One hon. Member just now pointed out an instance which occurred on the occasion of the swearing-in of the President. That was a ceremony attended by all manner of people, when distinguished guests from various parts are invited. That was not a formal function at all, that was not a Joint Session of the two Houses at all. So, the analogy cannot be with that function which took place when the President was sworn in. Therefore, I would submit that we have been landed in a very difficult situation. It is not a question of taking a lenient view of this lapse. A lapse has occurred on the most important occasion that there can be in the life of the Parliament, that is, the Joint Session of both the Houses. We cannot take a lenient view of this. Of course you may be pleased to reprimand them. That is something else but here is a problem of constitutional importance. It is a problem of a technical nature, that a stranger we can never allow to address and therefore, I would like you to stick to it although you might do any thing. Of course I find myself completely at sea to advise you on the present occasion because this is an unforeseen circumstance altogether. In these matters, if the Government consults the Opposition also previous to the Address, because the Address had to be read out, then probably we could have

advised them that the Vice-President must be invited to do it but I do not know what manner of consultations take place on an occasion like this. On no occasion we find that there is any consultation on any vital matter so far as the opposition is concerned. So far as the other side of the House is concerned, it has landed us in this trouble and we would like that you should give serious thought to this before giving any ruling on this matter because, in this matter, nothing less than the dignity of the House and a matter of serious constitutional importance is involved. I would like to underline this, I would like to go on record, that you might do anything but nobody has any right to ride roughshod over the Constitution, over the rules and conventions which should guide an important occasion like this.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, a constitutional point has been raised...

MR. CHAIRMAN: Mr. Gupta, you have already spoken. Please sit down. Mr. Shah.

SHRI BHUPESH GUPTA : Members should get some guidance. Where does the Constitution say that the Vice-President can address? He does by courttest...

MR. CHAIRMAN : I ask you to sit down when I am standing. Mr. Shah.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI K. K. SHAH) : It is most painful that the Leader of the Opposition should have allowed himself to be swayed by any other consideration. Are there two Addresses or is there one Address only ? This is what we have to consider. The Constitution provides that there shall be an Address by the President. Therefore, there cannot be two Addresses, one in English and one in Hindi. The President has a right to address in English or in Hindi. He can choose to address in English and then there shall be a translation of it in Hindi. He can choose to address in Hindi and there can be a translation in English. Surely it is not contended by my friends in the Opposition that the translation shall be made by the Vice-President. I cannot understand what my friends are saying. There cannot be two Addresses. I take it as a question of dignity that my Vice-President does not translate the speech of the President. On the contrary dignity demands that the Vice-President should not be called upon translate a speech which is either in English or Hindi.

MR. CHAIRMAN : I am giving my ruling now. I have heard enough.

SHRI GODEY MURAHARI (Uttar Pradesh) : Sir, I want to say a few words.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : (Rajasthan) : Sir, I also want to say something.

SHRI GODEY MURAHARI : Sir, I must have my say.

MR. CHAIRMAN : All right.

SHRI GODEY MURAHARI : Sir, Mr. K. K. Shah has made the point that only the President is authorised to address a joint session of the two Houses, and I agree with him that only the President is so authorised, and if the President so desires, the Vice-President shall exercise the authority of the President. So that position is very clear. But how does the Constitution allow the Secretary or any other individual, apart from the President, to read or even translate an address to be delivered by the President to a joint session of Parliament? That is my point. On former occasions, when the President delivered his address in English, he made it a practice to ask the Vice-President to translate it—and he did the translation—but he never asked his Secretary or any other individual to do it. So the point is that no other individual than the President, or the Vice-President exercising the authority of the President, can address a joint session of Parliament. This is the point.

**श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर उस प्रसंग पर उपस्थित हुआ है जब कि राज्य सभा के सचिव को राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति राज्य सभा के पटल पर रखने का आपने आदेश दिया था। सचिव को किसी भी कागज को सदन की मेज पर रखने के लिए कुछ नियमों का या कुछ वैधानिक बातों का पालन करना होता है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अंग्रेजी में हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण हिन्दी में नहीं हुआ। हिन्दी में दिया गया सैन्ट्रल हाल का भाषण एक स्ट्रेन्जर द्वारा था और एक स्ट्रेन्जर का दिया हुआ भाषण राज्य सभा का सचिव सभा पटल पर नहीं रख सकता है।

राष्ट्रपति के भाषण का अनुवाद एक स्ट्रेन्जर नहीं कर सकता है, वह तो कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करें और वह सदन के लिए स्ट्रेन्जर न हो। अगर उनका भाषण एक स्ट्रेन्जर द्वारा पढ़ा गया तो उसके द्वारा पढ़ा हुआ भाषण एक अधिकृत भाषण के पत्र रूप में सभा पटल पर रखने के लिए सचिव को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि सचिव को अनुमति देते समय आप अंग्रेजी में दिये गये भाषण की प्रति रखने की अनुमति दे सकते हैं। यह तो पहला मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा मेरा संवैधानिक है और जिसको आपने इस सदन की कार्य प्रणाली के तौर पर मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दे के निर्णय के रूप में स्वीकार किया था कि जब तक किसी पत्र की, हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में प्रतियां सदन पर न रखी जा सकें तब तक उस पत्र को रखने की इजाजत न दी जाय। मेरा आप से निवेदन है कि अंग्रेजी के भाषण की, क्योंकि उसकी अधिकृत प्रति हिन्दी में नहीं है, न ही वह हिन्दी में पढ़ी गई है, इसलिए आप यहां पर सचिव को उस अंग्रेजी की प्रति भी रखने की इजाजत न दें जब तक हिन्दी की अधिकृत प्रति रखने का उन्हें विधिवत अधिकार न मिले और इस तरह से कोई भी प्रति इस समय सदन पर नहीं रखी जा सकती है।

मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ, फिर भी इस समय कौन सी सिचुएशन पैदा होगी, उसका इलाज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को सदन की पटल पर रखने की जो वैधानिक संज्ञा है वह किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसके लिए आप कोई और व्यवस्था करें। लेकिन जब तक वह भाषण वैधानिक रूप से रखे जाने योग्य नहीं है तब तक आप सचिव को उनके भाषण की प्रति सभा पटल पर रखने की इजाजत न दें।

MR. CHAIRMAN : Now I shall give my ruling.

SHRI BHUPESH GUPTA : There is a point of order, a new point of order.

MR. CHAIRMAN : No more. I have heard enough. I must give my ruling now.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I want a Hindi translation of the speech and also I would like a Bengali translation of it.

MR. CHAIRMAN : Please sit down, Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI M. R. VENKATARAMAN (Tamil Nadu) : Sir, I am going to take exactly two minutes and no more, and with due respect I am making only a practical suggestion with no idea to collide just now on any constitutional point—I am also a constitutional lawyer in a small way but that does not matter since I am not going into any constitutional point now. My request now is that the practical suggestion that I make be heard and approved of by the House. Now the address has been read in English and a translation of it in Hindi has been made available to the other friends who wanted it in Hindi also, so that they know the contents of the address in Hindi. The only objection now, as far as I see, is that his Secretary has read the address in Hindi or made the translation of the address in Hindi, whatever it is. Now, had it been the other way about—I am assuming a hypothetical position—that the President delivered his address in Hindi and the translation was in English, the position would be much the same as I see it now, that is to say, in the other language, in the alternative language. In the additional language—whatever name you give it—the material is available to the rest of the Members of the House. Therefore I would appeal to the House to take my suggestion. My friend, Mr. S. N. Mishra, also talked about the constitutional implications. Of course I am worried about them and I can understand the concern with which the point has been raised. Now the Constitution is on the anvil and let not any bad precedent be set up today. A day will come when I will insist on its being read in Tamil as well as in the fourteen other national languages of India. Now I appeal to my friends to treat it as a practical issue today and leave it at that, and let us get on with the work,

MR. CHAIRMAN : Yes, thank you.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, हम उनकी भावना के साथ हैं, लेकिन यहां पर हिन्दी और तामिल का मामला नहीं है। यहां पर तो वैधानिक कन्वेंशन का सवाल है।

SHRI ANANT PRASAD SHARMA (Bihar) : Sir, as has been pointed out, I want to emphasise the point that the President has addressed the joint session in English and his speech has been simultaneously translated by his Secretary. It is good that it has been translated by his Secretary because I know personally and most of us know about the competence of the Secretary regarding the Hindi language. Now, it would have been quite in order if that translation had been made by any other person. What is wrong there? You look at the national and international conferences and the arrangements for translation there.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, हमारा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है क्योंकि जितना ये बोले हैं, उसमें हमारा प्वाइन्ट आफ आर्डर हो गया है।

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Please sit down now, Mr. Rajnarain.

SHRI ANANT PRASAD SHARMA : My friend has rightly pointed out that we speak in a particular language and it is being translated in so many languages. Now are we going to insist that the translator should be a Member of Parliament because a Member of Parliament's speech is going to be translated? Moreover, Sir, there is no such provision laid down anywhere in the Constitution how this speech has to be translated. Therefore, Sir, I maintain that whatever has happened is quite in order, is absolutely in order, and the points of order to the contrary should be disallowed.

MR. CHAIRMAN : Now the standing Members will please sit down. I have heard enough and I shall now give my ruling. The President addressed the joint session. Under his orders his address was translated by his Secretary. It was under his orders. His Secretary might not have translated it. The translation in Hindi, the authorised

translation, is supplied to the hon. Members. It is not proper for me to comment on the President's act.

SHRI S. N. MISHRA: But may I suggest...

MR. CHAIRMAN : Please listen to me first; I am giving my ruling. For the future what will happen will be considered by me within the limits of my office and today's debate will be placed before the President.

SHRI BHUPESH GUPTA : I hope, Sir...

MR. CHAIRMAN : You may hope but let me finish. Please listen.

So far as today's proceedings are concerned I rule that the English Address along with the Hindi translation will be laid on the Table of the House.

SHRI BHUPESH GUPTA : I request that the Vice-President should not be reduced to the status of a translator.

SHRI PIT AMBER DAS (Uttar Pradesh): Sir, I want to say a word; I would like to bring to your kind notice one thing, not by way of a criticism of your ruling. Since your ruling would go on record there is a word in that, which I want to submit to you, you might reconsider. You have said that the President is the head of Parliament. He is part of Parliament under article 79. He is head of the State, not of Parliament.

MR. CHAIRMAN : All right; I will consider that.

SHRI PITAMBER DAS : He is part of Parliament, not its head.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am happy that you did not read it because in that case your status would have been reduced to that of a translator which as a Rajya Sabha Member I would never accept.

SHRI S. N. MISHRA : Sir, I have one very humble submission to make. You have given a ruling which gives to the President even the right to act against the Constitution.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

SHRI S. N. MISHRA : Let me make my point. Now, Sir, the President is there to

preserve, protect and defend the Constitution. The Constitution lays down that no stranger can address us. It is only the President... *(Interruptions)* Please listen; this is a matter of Constitution. The Constitution lays down that only the President can address us; no stranger can address us. Now, Sir, extending the logic that you have been pleased to place before us, probably the President sitting in Rashtrapati Bhavan can ask any person to deliver the Address on his behalf...

SOME HON. MEMBERS : No, no.

SHRI S. N. MISHRA : So for the future I would like this to be placed on record that we raised three points. *(Interruptions)* Please listen to me.

MR. CHAIRMAN : That is all over now.

SHRI S. N. MISHRA : I am winding up.

SHRI SRIMAN PRAFULLA GOSWAMI(Assam) : Sir, let him not waste the time of the House.

*(Interruptions)* SHRI S. N. MISHRA : This is not the way. We would like to go on record that we have taken a strong objection to a stranger having addressed the joint session of Parliament. That is point No. 1. We have also taken strong exception...

MR. CHAIRMAN : I have already told you that the whole proceeding will be placed before the President. We treat it as a translation and take it as such, and there is no problem involved in it.

SHRI S. N. MISHRA : Since one of our hon. Members has raised this point and many other hon. Members also supported it, in all fairness I would like to submit most humbly to the hon. Members that this was not a question of English versus Hindi or anything of that kind. We would not have liked if the speech had been made by a stranger even in Tamil or in Telugu or some other language. We are not bringing in that point at all.

And thirdly we would like to go on record that we did not anticipate at all and we would not like it to be the practice in future that the Vice-President should be ignored in this matter and we have had absolutely no reason from the other side as to why the Vice-President has been ignored. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN : I have given my ruling; nothing else now. Secretary shall lay the Address on the Table.

**श्री राजनारायण :** श्रीमन्, पाइन्ट आफ इनफारमेशन ।

MR. CHAIRMAN : Please sit down Mr. Rajnarain. I am standing; you have to sit down.

**श्री राजनारायण :** मैं आपसे कुछ इनफारमेशन मांग रहा हूँ । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रपति महोदय ने उपराष्ट्रपति महोदय से इस सम्बन्ध में कोई विचार-विनिमय पहले किया था ? हाँ कहिए, नहीं तो नहीं कहिए ।

**श्री सभापति :** इस वक्त यह आइटम खत्म हो गया ।

**श्री राजनारायण :** मान लीजिए कि राष्ट्रपति बीमार हो गए तो मिश्र जी का वह पाइन्ट आ गया कि राष्ट्रपति फिर क्या किसी को कह सकते हैं कि तुम हमारा एड्रेस पढ़ दो ।

**श्री सभापति :** आप समझते हैं कि मैं इसको कुछ नहीं समझूँगा ।

**श्री राजनारायण :** संविधान कहता है . . .

MR. CHAIRMAN : I do know *samvidhan*.

SHRI RAJNARAIN : And knowingly you are going outside the Constitution ?

**श्री सभापति :** मैं कांस्टीट्यूशन के बाहर नहीं जा रहा हूँ । I am asking you to sit down.

**श्री राजनारायण :** मैं जानता हूँ कि आप संविधान जानते हैं लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जानते हुए भी आप संविधान का उल्लंघन न करें ।

**श्री सभापति :** जो आपने कहा वह मैंने सुन लिया, फिर सुन लूँगा, इस वक्त रहने दें ।

**श्री राजनारायण :** इस वक्त अन्याय होने है ?

**श्री सभापति :** इस वक्त अन्याय नहीं हो रहा है ।

Secretary to lay it on the Table.

SECRETARY : Sir, I lay on the Table a copy of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 20th February, 1970.

*(Text of the President's Address in English)*

Members of Parliament, I welcome you to your labours in a new Session of Parliament. I wish you another year of dedicated work in the service of our country.

This is the first Budget Session of a new decade. Behind us lies the decade of the sixties. This period has been one of anxiety, of trials and tribulations and also of achievement. India had to face two wars and two years of unprecedented drought. All citizens stout-heartedly faced this period of trial. The wars brought home to us the inescapable necessity for self-reliance and the drought focussed our energies on augmentation of agricultural production. Indeed, a new strategy for agricultural development was implemented during this period and its success has attracted world-wide attention.

The challenge posed by the industrial recession was also met in a variety of ways. Many industrial units began diversifying their production. The search for markets for our goods was intensified.

Taking stock of our record during the period beginning with our independence and ending with the decade of the sixties, Hon'ble Members will recognise the range and scope of our country's achievement in industry and agriculture, in science and technology, and in education and the arts.

The path of progress tends to be uneven and beset with reverses, frustrations and hardships. However, our country today is no longer stagnant. It is in ferment. The aspirations of our people and their hopes have been aroused. "They are vocal and impatient—conscious of their needs and rights. Against the background of a highly stratified society, which had been invented the perverse concept of untouchability, we now see the pride and self-assertion of groups and classes who once were regarded as beyond the pale.

There has been an unleashing of a vast amount of human energy and enthusiasm. Ideas, attitudes and even habits are rapidly changing. And this transformation is tak-



ing place by consent and within the framework of a political democracy. Government are determined to give to these vast forces which have been unleashed by the developments of the last two decades, a new sense of direction and purpose as well as a realisable goal.

Government are acutely aware of the inequalities in the country which become glaring when contrasted with the prosperity of some sections of the community. Consequently, change in the social structure and the removal of poverty are two aspects of the same question. One cannot be achieved without the other.

Government are resolved to go forward at a faster pace towards the achievement of a social order which is just and humane, by taking particular care of the weaker sections of the community and by ensuring that the meagre wealth of the nation is augmented by hard and dedicated work. It is my Government's unswerving purpose to build, brick by brick a society which is democratic and socialist. The task is long and hard and there are no models to copy. The problems of India require uniquely Indian solutions, taking into account our way of life, our history and our tradition.

The present economic situation in the country augurs well for the acceleration of the pace of development. Despite the deficiency of the monsoon in some parts of the country such as Western Rajasthan, Saurashtra and Kutch, and the somewhat belated onset of winter rains, it should be possible to reap an even better harvest than during the past two years. While the movement of prices has been subject to seasonal fluctuations and some increase has been noticed in respect of certain commodities, the price situation is on the whole well under control. The food position is satisfactory and we have been able to augment our buffer stocks. However, constant vigilance is necessary to maintain price stability. The balance of payments has remained satisfactory and we should be able to end the year with an increase in reserves even after substantial repayments to the International Monetary Fund. We have also received the first instalment of the Special Drawing Rights which marks an important advance in the evolution of a rational international monetary system.

industry in general has registered satisfactory growth, and the outlook, especially in the engineering field, is now distinctly more favourable.

The Central and State Governments have further intensified their efforts to raise agricultural production under the new strategy. The area under high-yielding varieties has risen from 1.9 million hectares in 1966-67 to about 9 million hectares in 1968-69. The coverage will be extended further in 1969-70. For the first time the supply position of fertilizers in the country is comfortable. We are formulating measures to promote their increased use. The gathering momentum of the technical transformation of our agrarian economy is evident in the keen demand for tractors which Government are striving to meet through maximum indigenous production and large scale imports. A big programme for the setting up of agro-service centres by small entrepreneurs, particularly engineers and technicians, is proposed to be implemented vigorously with assistance from the banking sector.

Rural electrification programmes, in conjunction with the exploitation of ground water resources have an important part to play in stepping up agricultural production and in dispersing its benefits widely. State Electricity Boards have been enabled to borrow from the banking system on a bigger scale in the wake of nationalisation. A significant part of these resources will be utilised by them for the extension of electricity to rural areas. Hon'ble Members are also aware that a Rural Electrification Corporation has been formed to provide funds to the Electricity Boards so that they can energise a larger number of pump sets for lift irrigation.

The break-through in agriculture which is at present limited to irrigated areas growing high-yielding varieties has to become universal. In the coming years, Government will concentrate their attention on the problems of the dry areas. While research on the development of suitable technology for dry areas will receive high priority, my Government propose to begin with a few pilot projects in different parts of the country to implement a package of new practices and to enlarge the programme progressively.

My Government have decided to appoint a National Commission to survey the problems and policies relating to agriculture. Such a survey was last made forty years ago. Since then a great many developments have taken place, both in India and abroad, which render a fresh survey essential. My Government have also decided to set up a Committee of Enquiry to make a comprehensive study of the problems of the sugar Industry.

Government are deeply conscious of the developing imbalances in the countryside and the resulting tensions which have regrettably led to violence in some parts of the country. These are no doubt problems of public order but they cannot be divorced from their socio-economic setting. An unfair tenurial system impedes the attainment of a high rate of growth in agricultural production. Hence, all State Governments have been asked to accord high priority to land reforms, with special emphasis on security of tenure, fair rents, strict enforcement of ceilings, distribution of land to the landless and assured supply of agricultural inputs to small farmers. The problems which are associated with land reforms are of national importance. My Government earnestly hope that the States will see the realities of the situation and take urgent and imaginative remedial measures. The vigorous implementation of land reforms will also promote the social and economic advancement of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, whose welfare is of special concern to my Government.

After the set-back in 1966 and 1967, there has been a significant increase in the tempo of industrial activity. Present indications are that industrial production will have increased by a little over 7% in 1969. A particularly heartening feature of the current industrial situation is the recovery noticed in a large number of industries manufacturing capital goods and equipment.

Government have formulated a new licensing policy in the light of the recommendations of the Industrial Licensing Policy Enquiry Committee. This policy seeks to promote industrial growth while embodying adequate safeguards against monopolistic trends and the concentration of economic power. The encouragement of new entrepreneurs, small and medium, is one of

its important features. Government are also keen to encourage the growth of small-scale industries. The list of industries reserved for the small-scale sector has therefore been enlarged.

My Government are of the view that there is considerable scope for large-scale industrial units in the public as well as in the private sectors, to farm out the production of components to ancillary units. Government's licensing and financial policies will seek to encourage coordinated development of large and small-scale industries. The need to redress regional imbalances has also received the special attention of the Government in the last few months. An integrated policy has been evolved to identify industrially backward areas and give them special incentives for industrial development.

The policies of financial institutions are being progressively reoriented towards the promotion of industries in backward areas. While these policies are designed to accelerate the flow of finance for industrial development in backward areas, they will succeed only in so far as the requisite infrastructure is built up imaginatively and speedily. The primary responsibility in this regard is that of State Governments and it will be the endeavour of my Government to work in close harmony with them in promoting balanced regional development.

The revival of industrial production in the current year is reflected in the increased demand for steel and steel products. While arrangements had to be made for imports of steel to meet, to an extent, the pressing shortages, it is our aim to maximise production in existing plants and establish additional capacity as early as possible.

Government have now decided to take in hand immediately the work on the second stage of the Bokaro Plant. Indeed it is our objective to initiate action for the establishment of other steel plants also at suitable sites so as to ensure the fruition of additional capacity according to a phased programme. The Fourth Plan, which is now being recast, will reflect the current thinking of Government on the possibilities of further expansion of steel capacity in the country. An important consequence of these decisions will be the fuller utilisation of capacity in our heavy engineering units.

Oil exploration is another important element in our strategy for economic self-reliance. Progress has been maintained in the current year in the exploration and production of oil. The aggregate production of crude oil during 1969 was 6.7 million tonnes as against 5.8 million tonnes in the previous year. A specially significant development has been the extension of exploration to the off-shore areas of the Gulf of Cambay. We expect to spud the first well in shallow waters shortly and are poised to undertake the preparatory work to begin exploration in the deep waters of the Gulf of Cambay. Production has already commenced in the Oil and Natural Gas Commission's off-shore joint venture with Iran.

Apart from steel and oil, the production of fertilisers has been given the highest priority in our Plan. During the current year, two new fertiliser plants have gone into production, raising the total installed capacity to 1.34 million tonnes of Nitrogen. Three more projects—in Durgapur, Cochin and Madras—with a total capacity of nearly 500,000 tonnes are expected to be commissioned during 1970. Work on coal-based plants will also commence shortly. We shall continue to pursue self-sufficiency in this important field with unabated vigour.

A steady and significant increase in our exports is essential to maintain the momentum of development. Last year witnessed very gratifying progress towards external viability. Despite the recent pick up in industrial recovery, imports have continued to fall, thus affording some evidence of the success of import substitution. Exports, however, have not done so well in the first seven months of the current year, for a variety of reasons, external and internal. My Government have, therefore, undertaken a crash programme to increase exports as much as possible.

In securing a better equilibrium in our balance of payments, earnings on invisible account are of very great importance. During the year, certain progress has been registered. It is gratifying to note that a larger number of tourists visited India during 1969 compared to 1968, resulting in an increase in our foreign exchange earnings on this account from Rs. 27 crores to roughly Rs. 32 crores. Likewise, with the steady

increase in our shipping tonnage, our overseas trade is being carried in a larger measure by Indian ships whose share is at present between 18 and 20 per cent.

A perceptible increase in the standards of living of our people is also linked with the vigorous implementation of family planning programmes. The rising rate of population erodes the gains of development. Our family planning programme has gained momentum in the last four years. But very much more needs to be done if the national aim to reduce the current birth rate of 39 per thousand to 25 per thousand in a decade is to be achieved on time.

Increased production and better distribution of wealth and income generating opportunities for employment should be the parameters of our economic policy. These priorities will be reflected in the Fourth Plan document which will shortly be finalised and placed before you. My Government are aware that unemployment is the most serious problem facing the economy and an early and effective solution to it must be found. The increase of 2% in employment in the organised sector after comparative stagnation in the two preceding years is an encouraging factor.

The selective increase in the level of outlays now envisaged in the public sector in the Central and State Plans have, among other things, been inspired by Government's desire to enlarge opportunities for employment. At the same time, special steps have to be taken to impart an employment bias to development. Programmes with large employment potential, will be identified and given a special impetus. Some steps have already been taken towards this end. In the current year, the States have been enabled to earmark larger outlays for programmes such as major and minor irrigation, and rural electrification which provide employment to a large number of engineers and technicians. Land reclamation, the renovation of minor irrigation works, construction of roads linking villages with marketing centres and similar programmes can make a substantial impact on rural development and employment.

A large scale rural works programme, pooling together the resources available under the Plan, will be drawn up and impl

mented vigorously within a period of 12 to 18 months. This is a task which calls for much detailed planning and local initiative at State level. Construction activity can also contribute to employment among engineers, technicians, skilled and unskilled workers. My Government therefore propose to direct larger resources towards programmes such as the bulk acquisition and development of land for the allotment of house sites, housing for low income groups and slum clearance, particularly in metropolitan areas where the housing problem is most acute.

Our technical education programmes have to be reoriented so as to subserve the needs of employment. The education now imparted in our polytechnics has to be linked with practical experience in industry. This involves a fundamental change in education in polytechnics so that theory can be related to practice and teaching to industrial work. We have simultaneously to provide greater opportunities to other students also to gain work experience. The programme of national service for students studying in the first two years at degree level is now proposed to be expanded to cover all universities on a selective basis. It is expected that nearly one lakh students will participate in the scheme. The students will thus get an opportunity to engage in social service and in the process acquire a sense of involvement in various national development programmes.

Greater employment will thus result from investment, which in turn calls for the mobilisation of larger savings. This will be one of the important objectives of nationalised banks. With their present bold programme for branch expansion, they are expected to mobilise deposits on a much larger scale than hitherto. At the same time, assistance for viable and productive schemes will flow from the banks in a greater measure to the weaker sections of society. The spirit underlying the policy of nationalisation is beginning to inform the activities of the banks which have begun to assist productive and gainful activities in agriculture, servicing industries and the retail trade which had so far been grievously neglected. The salutary processes, which have already been initiated, will be further activated when legislation regarding the nationalisation of banks is suitably re-enac-

ted in the light of the recent judgment of the Supreme Court.

I should like, at this stage to refer to Government's labour policy. It has always aimed at ameliorating the living and working conditions of labour, improving their wages and emoluments and assuring them a degree of job security. In pursuance of this policy, Government have recently decided to accept the principal recommendations of the Wage Boards on Ports & Docks and have encouraged the setting up of a bipartite negotiating machinery for revision of the wage structure in the iron and steel industry. The National Commission on Labour, whose report the Government have recently received, has made several recommendations for strengthening the Trade Union movement and promoting effective collective bargaining. My Government specially appeal to all sections of organised labour to support the efforts of Government in stepping up production and productivity. Without discipline and sustained and hard work, the country cannot achieve its socio-economic goals.

But all these efforts at socio-economic advancement can succeed only in an environment of peace and harmony, and a firm adherence to democratic principles. The continuing trend towards violence in the country is, therefore, a cause of deep concern. The problem transcends political divisions and the Government seek the co-operation of all political parties, and indeed of all responsible citizens, in dealing with it.

Of all the manifestations of violence the most disturbing, because it is destructive of all values of civilised life, is the one between different religious communities. After the meeting of the National Integration Council in 1968, there were signs of improvement in communal relations. But then came the shocking happenings in Ahmedabad, causing national humiliation and leaving a blot on our honour. Those happenings are a challenge to all who have faith in secularism and the dignity of the individual, and respect for human life. We view with particular concern the continuing resort to violence by certain extremist political groups. At the root of their activities is a political ideology which exploits social discontent to pursue its disruptive aims.

While we are anxious to remove genuine causes of social discontent, violent activities have to be dealt with firmly.

At a critical period in our history, the Princes showed patriotism and imaginative understanding of the aspirations of the people and made a major contribution to the smooth and peaceful unification of India under a democratic regime. I have every hope that in the same way they will recognise the social imperatives of the present times and, in the wider interest of the country, once again exhibit a spirit of co-operation and goodwill. The concept of Rulership, with privy purses and special privileges unrelated to any current functions and social purposes, is incompatible with an egalitarian social order. Government have, therefore, decided to abolish the privy purses and privileges of the Rulers of the former Indian States, and legislation will be introduced to give effect to this decision. It is, however, our intention to make certain transitional arrangements so that the former Rulers may have time to adjust themselves to changed circumstances.

My Government earnestly hope that the decisions regarding Chandigarh and part of the Fazilka tehsil will enable the people of the two neighbouring States to devote their energies to the constructive tasks which lie ahead. When emotions are aroused, a decision capable of satisfying everyone is not possible. But it is Government's belief that the decisions reached have been just and fair. Government will soon appoint a Commission to go into other claims by Punjab, Haryana and Himachal Pradesh for the re-adjustment of their present boundaries and will also consider such modifications as are necessary in the present arrangements relating to the management of the Bhakra Project and the construction of the Beas Project.

Our next decennial Census of population will be held early in 1971, marking the completion of a hundred years of census taking in the country. The Indian Census is the largest administrative operation of its kind in the world and the success of an operation of such intricate nature and magnitude is possible only through the co-operative effort of the Central and State Governments, local authorities, and, indeed, of every citizen.

In the sphere of external affairs, we have sought to promote and further strengthen our friendship with other countries. We continue to adhere to the pursuit of peace, international understanding and mutually beneficial co-operation.

The concept of peaceful co-existence has been steadily gaining acceptance. We feel that the area of peaceful co-existence should steadily be widened and given a new dimension of friendly co-operation. We believe that, with the lessening of the rigidities of the military blocs and easing of tensions between the power blocs, there is now greater acceptance of the concept of non-alignment and widening of the opportunities to advance the cause of the freedom, prosperity and stability of nations.

It is a matter of gratification that our relations with our neighbouring countries—Ceylon, Burma, Nepal, Afghanistan and Iran—have been developing fruitfully. New vistas of mutual co-operation and understanding continue to be discovered with these and other countries.

It has been Government's policy to pay increasing attention to the development of our bilateral and multilateral economic relations with all countries. We are paying particular attention to promoting such relations with the developing countries in general and the countries of the Asian region in particular. Now that agricultural and industrial development of India has reached a significant stage, it is possible for our country to make a contribution to international co-operation. We have, therefore, supported the setting up of a broad-based regional arrangement through the Council of Ministers for Asian Economic Co-operation under the ECAFE.

Government earnestly desire the understanding, cooperation and friendship of the people and Government of Pakistan. We have made various suggestions and constructive proposals to the Government of Pakistan to break the present impasse. Unfortunately, there has been no positive response from Pakistan to the initiatives we have taken. My Government will persevere in their efforts to promote relations with Pakistan in a co-operative spirit and on the basis of amity and good neighbourliness.

With China also our aim has been to conduct our relations on the principles of mutual respect of each other's sovereignty and territorial integrity and non-interference in each other's internal affairs. We expect China to respect our right to pursue our own domestic affairs and foreign policy.

My Government are deeply concerned that the conflicts in West Asia and in Vietnam have remained unresolved. Both these conflicts have an unsettling effect on the peace and stability of the world. The tensions in West Asia are reaching a dangerously explosive level. It is necessary for the U.N. to ensure implementation of the Security Council Resolution of November 22, 1967. In Vietnam, the hostilities still continue. My Government have consistently advocated the withdrawal of all foreign forces so that the people of Vietnam are able to fashion their own destiny without any outside interference.

We have had the privilege of receiving many distinguished Heads of States and Governments in our midst. During the past year, I visited our friendly neighbour Ceylon and the Prime Minister visited Burma, Afghanistan, Japan and Indonesia. These visits contributed to the growing understanding and friendship with these countries.

We are dedicated to the cause of peace but have to be vigilant to maintain our defence preparedness at a high level. Steady progress has been made in achieving self-reliance in equipping our defence forces. A self-supporting industrial base for defence is being built up in the country. We are now self-reliant in respect of many important categories of arms and ammunition. We have also made appreciable progress towards indigenous production in the vital fields of electronics, aeronautics and construction of warships.

The estimates of receipts and expenditure of the Government of India for the next financial year (1970-71) will be presented to you for consideration shortly.

Government will bring before Parliament a Bill for replacing the recent Ordinance re-nationalising the 14 banks. A Bill is already pending in the Rajya Sabha which will replace the Essential Commodities (Amendment) Continuance Ordinance, 1969. Government also propose to bring forward

a Bill in replacement of the Haryana and Punjab Agricultural University Ordinance, 1970. Government also intend to bring before Parliament the following legislative measures during the current session :—

1. A Bill to amend the Press Council Act.
2. The Prevention of Insults to National Honour Bill, 1970.
3. The Foreign Assistance (Regulation) Bill, 1970.
4. The Crop Insurance Bill, 1970.
5. A Bill to set up a Newspaper Finance Corporation.
6. A Bill to amend the Untouchability (Offerees) Act, 1955.
7. The National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 1970.
8. A Bill to set up an autonomous statutory corporation for the management of the four international airports in India.

Members of Parliament, you meet at a moment of great expectations among our people. May you truly reflect their urges and aspirations, and may your deliberations and wisdom bring them nearer fulfilment.

*(Text of the President's Address in Hindi)*

संसद सदस्यगण, संसद के इस नए अधिवेशन में आपके कार्यों की सफलता के लिये मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरी कामना है कि आप अगले वर्ष भी देश की सेवा में निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें।

यह नए दशक का पहला बजट अधिवेशन है। 1969 में समाप्त होने वाला दशक हम पीछे छोड़ आये हैं। इन दस बरसों में चिन्ता, कष्ट और संकट का सामना रहा, लेकिन कुछ उपलब्धियाँ भी हुईं। भारत को दो लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और यहाँ दो बरस तक अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रही। सभी देशवासियों ने बड़े हीसले के साथ इन मुसीबतों का सामना किया। लड़ाइयों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और सूखे की स्थिति के फलस्वरूप हमने संकल्प किया कि हम कृषि उत्पादन को

पूरी शक्ति के साथ बढ़ावें। निस्संदेह, इस अवधि में कृषि-विकास के नए कार्यक्रम पर अमल किया गया जिसकी सफलता पर सारे संसार के देशों का ध्यान आकर्षित हुआ।

उद्योगों में मंदी के कारण जो चुनौतियाँ आईं, उनका भी कई तरीकों से मुकाबला किया गया। बहुत से उद्योगों ने अपने उत्पादन में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया और हमारे माल के लिये नई मंडियाँ खोजने की कोशिशें और बढ़ा दी गईं।

यदि आजादी से 1969 तक की हमारी उपलब्धियों का लेखा-जोखा लिया जाए, तो माननीय सदस्यगण इस बात को मानेंगे कि हमारे देश ने उद्योग और कृषि, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान तथा शिक्षा और कला के क्षेत्रों में व्यापक उन्नति की है।

प्रगति का मार्ग सदा सरल नहीं बल्कि उसमें असफलता, निराशा और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा देश आज गतिहीन नहीं है। वह गतिमान हो गया है: लोगों की आशाएँ और आकांक्षाएँ बढ़ गई हैं। वे मुखरित और अक्षम हो उठे हैं— अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। ऐसे समाज में जहाँ ऊँची-नीच की भावना इस सीमा तक रही कि जिसमें अस्पृश्यता की भ्रष्ट विचारधारा पनपी, अब हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के लोगों में आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास की भावना आ गई है।

लोगों में बड़ी ताकत आई है और जोश पैदा हुआ है। विचार, रख और आदतों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पर यह जन-सहमति से और राजनैतिक लोकतंत्र के ढाँचे के अन्तर्गत ही हो रहा है। पिछले बीस बरसों के विकास कार्यों से उत्पन्न इन शक्तियों को एक नई दिशा, उद्देश्य और प्राप्य लक्ष्य देने के लिये भारत सरकार कृत-संकल्प है।

सरकार को इस बात का पूरा ज्ञान है कि देश में असमानताएँ हैं जोकि कुछ धनी वर्गों

के सुख-समृद्धि की पृष्ठभूमि में और भी प्रखर हो उठती है परिणामस्वरूप, सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन और गरीबी का उन्मूलन एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं। किसी एक की प्राप्ति दूसरे के बिना नहीं हो सकती।

सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी जो न्यायपूर्ण एवं मानवीय भावना से ओतप्रोत हो। ऐसा करते समय वह समाज के गरीब वर्गों का विशेष ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्र की जो भी थोड़ी-बहुत सम्पदा है, उसे कड़े परिश्रम और निष्ठा से काम करके बढ़ाया जाय। मेरी सरकार का यह उद्देश्य है कि उसका हर कदम देश को एक समाजवादी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के गंतव्य की ओर अविचल ले जाए। यह काम लम्बा और कठिन है। न ही हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण है जिससे मार्गदर्शन हो सके। भारत की समस्याएँ ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने के लिये हमें अपने तीर-तरीकों, इतिहास और परम्परा को ध्यान में रखते हुए विशुद्ध भारतीय समाधान खोजने होंगे।

देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति विकास की गति को बढ़ाने के लिये बहुत आशाप्रद है। देश के कुछ भागों में, जैसे पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में मानसून की कमी और जाड़ों के मौसम में कुछ देरी से वर्षा होने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी फसल होगी। यद्यपि चीजों की कीमतों में समय के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहा है और कुछ चीजों की कीमतों में कुछ वृद्धि होती भी दिखाई दी है, तो भी सब कुछ देखते हुए कीमतें अच्छी तरह नियंत्रण में हैं। खाद्य स्थिति सन्तोषजनक है और हमने अपने भण्डार में वृद्धि की है। फिर भी कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिये निरन्तर देखभाल करना जरूरी है। शोधन संतुलन सन्तोषजनक रहा है और वर्ष के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मानि-

टरी फंड) को पर्याप्त अदायगी करने के बाद भी आरक्षित-कोष में वृद्धि ही होगी। हमें विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की पहली किश्त भी मिल गई है जिसके कारण युक्तिसंगत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के विकास को महत्वपूर्ण गति मिली है। उद्योग में सामान्यतः संतोषजनक वृद्धि हुई है और विशेष तौर से इंजीनियरी के क्षेत्र में स्थिति स्पष्टतया अच्छी हो गई है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नये कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेती-बाड़ी की पैदावार को बढ़ाने में अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। अधिक उत्पादन करने वाली फसलों का क्षेत्रफल 1966-67 में 19 लाख हैक्टेयर था, वह 1968-69 में बढ़कर लगभग 90 लाख हैक्टेयर हो गया। 1969-70 में यह क्षेत्रफल और बढ़ जायेगा। देश में पहली बार खाद सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हुआ है और हम खाद का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। ट्रेक्टरों की बढ़ती मांग से यह स्पष्ट है कि हमारी कृषि व्यवस्था में तकनीक का स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेक्टर बनाकर और बड़ी मात्रा में उन्हें विदेशों से मंगाकर सरकार उस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। छोटे उद्यमियों, विशेषकर इंजीनियरों और तकनीशनों द्वारा कृषि-सेवा केन्द्र खोलने के एक बड़े कार्यक्रम को बैंकिंग क्षेत्र की सहायता से जोरों से कार्यान्वित करने का भी विचार है।

खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाने और व्यापक रूप से उसका लाभ वितरित करने की दृष्टि से गांवों में बिजली देने का कार्यक्रम तैयार करना और भूमि से जल निकालने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयकरण के बाद राज्यों के बिजली बोर्डों को बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेने की मुविधा दे दी गई है। इन साधनों का विशेष प्रयोग ये बोर्ड गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये करेंगे। माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक ग्राम बिजली निगम स्थापित कर दिया गया है जो बिजली

बोर्डों को धन देने की व्यवस्था करेगा ताकि वे उत्पादक सिंचाई के लिये बड़ी संख्या में पम्प-सेट चालू करा सकें।

कृषि विकास में उत्कृष्ट सफलता अभी तक उन सिंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है जिन पर अधिक उत्पादन करने वाली फसलें उगाई जाती हैं। उसे अब और व्यापक बनाना है। आगे आने वाले बरसों में भारत सरकार अपना ध्यान सूखे क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्रित करेगी। सूखे क्षेत्रों के लिये उपयुक्त तकनीक के विकास पर अनुसन्धान करने को तो प्राथमिकता दी ही जायेगी। साथ ही, मेरी सरकार का इरादा है कि कुछ नये तरीके अपनाने और धीरे-धीरे कार्यक्रम को व्यापक बनाने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में कुछ प्रमुख प्रायोजनाएँ (पाइलट प्रोजेक्ट) शुरू की जाएँ।

मेरी सरकार ने कृषि से संबद्ध समस्याओं और नीतियों का सर्वेक्षण करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है। अब से पहले ऐसा सर्वेक्षण चालीस वर्ष पहले हुआ था। तब से इस क्षेत्र में इतनी नई बातें हुई हैं कि नया सर्वेक्षण आवश्यक हो गया है। मेरी सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं का विशद अध्ययन करने के लिये एक जांच समिति स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

सरकार को इसका पूरा आभास है कि देहातों में असंतुलन बढ़ रहा है जिससे उत्पन्न तनावों के कारण देश में जहां-तहां हिंसात्मक उपद्रव हुए हैं। ये निस्संदेह सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याएँ हैं, तो भी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से हटाकर उन्हें नहीं देखा जा सकता। अनुचित काश्तकारी पद्धति से कृषि उत्पादन की वृद्धि में अड़चनें आना स्वाभाविक है। इसलिए, सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे काश्तकारी की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए, भूमि-सुधार, उचित लगान, जोत का निर्धारण, भूमिहीनों में भूमि वितरण और छोटे किसानों को कृषिगत वस्तुओं की आपूर्ति करने के कार्यों को अधिक



प्रार्थमिकता दे । भूमि-सुधार से सम्बन्धित समस्याएं राष्ट्रीय महत्व की हैं । मेरी सरकार को पूरी आशा है कि विभिन्न राज्य इस स्थिति की वास्तविकता पर ध्यान देंगे और इसे सुधारने के लिये तत्काल कदम उठाएंगे । भूमि-सुधारों पर तेजी के साथ अमल करने से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जन-जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा । मेरी सरकार को इस लोगों के कल्याण की विशेष चिन्ता है ।

1966 और 1967 में उद्योग के क्षेत्र में जो झटके आये थे, उनके बाद उद्योगों के कार्य-कलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई । वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1969 में औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ा होगा । वर्तमान औद्योगिक स्थिति की विशेष उत्साह-वर्धक बात यह है कि पूंजीगत माल और उपकरण तैयार करने वाले बहुत से उद्योग फिर से अधिक सक्रिय दिखाई देने लगे हैं ।

उद्योग लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एक नई लाइसेंस नीति बनाई है । इस नीति का उद्देश्य होगा—आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की भावना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना । छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहन देना इसकी प्रमुख विशेषता है । सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने को बहुत उत्सुक है । इसीलिये, लघु उद्योग क्षेत्र के लिये भारभित्त उद्योगों की सूची बढ़ा दी गई है ।

मेरी सरकार के विचार में पब्लिक और प्राइवेट, दोनों सेक्टरों में बड़े-बड़े उद्योगों के लिये इस बात की काफी गुंजाइश है कि वे अनुषंगी उद्योगों को पुर्जें बनाने का काम दें । सरकार की लाइसेंस और वित्त-सम्बन्धी नीतियों का उद्देश्य यह होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन दिया जाये । पिछले कुछ महीनों में सरकार

का ध्यान विशेष तौर से इस पर भी गया है कि प्रदेशों के असंतुलन को दूर किया जाय । उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों का पता लगाने और उनके औद्योगिक विकास को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक संगठित नीति बनाई गई है ।

पिछड़े इलाकों के उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में विनीय संस्थानों की नीतियों को धीरे-धीरे नया रुख दिया जा रहा है । यह नीतियां इस तरह बनाई जा रही हैं कि उनकी सहायता से पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास के लिये अधिक धनराशि तो मुलभ कराई जाये, लेकिन वे उस हद तक ही सफल हो सकेंगी कि उन उद्योगों के लिये जिस निचले ढांचे का निर्माण करना जरूरी है, वह जल्दी से तैयार कर दिया जाए । इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और मेरी सरकार संतुलित ढंग से प्रदेशों के विकास को समुन्नत करने में राज्य सरकारों के साथ निकट सामंजस्य रखकर काम करने का प्रयास करेगी ।

चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आरम्भ हुई है । यह इस बात से स्पष्ट है कि इस्पात और इस्पात से बनी चीजों की मांग बढ़ रही है । हालांकि उत्पादन में कमी को किसी हद तक पूरा करने के लिये बाहर से इस्पात मगाने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं—तो भी, हमारा लक्ष्य यह है कि वर्तमान संयन्त्रों से ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाए और जहां तक हो सके, जल्दी ही अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जाए ।

सरकार ने बोकारो प्लांट के दूसरे चरण का कार्य तत्काल आरम्भ करने का निर्णय किया है । निश्चय ही हमारा उद्देश्य यह होगा कि समुचित स्थानों पर अन्य इस्पात कारखाने लगाने का काम शुरू किया जाये जिसमें कि अवस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, अतिरिक्त क्षमता तैयार हो सके । आजकल जो चौथी योजना बनाई जा रही है, उससे पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार देश में इस्पात उद्योग

का और विस्तार करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इन निर्णयों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी होगा कि हमारे भारी इंजीनियरी कारखानों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकेगा।

आर्थिक आत्म-निर्भरता की दिशा में हमारे कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण अंग है—तेल की खोज। चालू वर्ष में तेल खोज निकालने और उसका उत्पादन करने में प्रगति हुई है। 1969 में कुल मिला कर 67 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ जबकि पिछले वर्ष 58 लाख मीट्रिक टन तेल का ही उत्पादन हो सका था। एक नई महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि कैम्बे की खाड़ी के तट से दूरके क्षेत्रों में भी तेल खोजने का काम आरम्भ कर दिया गया है। हमें आशा है कि हम जल्दी ही छिछले पानी में पहला कुआं खोद लेंगे और फिर कैम्बे की खाड़ी के गहरे पानी में भी तेल की खोज शुरू करने का प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लेंगे। ईरान एवं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का समुद्र तट से परे संयुक्त कारखाने में उत्पादन कार्य आरम्भ हो चुका है।

इस्पात और तेल के अलावा, हमारी योजना में खाद बनाने को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष में दो नए खाद संयंत्रों से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है और नाइट्रोजन की कुल स्थापित क्षमता बढ़ाकर 13.4 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है। आशा है कि 1970 में दुर्गापुर, कोचीन और मद्रास में 500,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले तीन और कारखाने काम करना शुरू कर देंगे। कोयला-आधारित संयंत्रों पर भी काम जल्दी ही आरम्भ हो जाएगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम पूरे जोश के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

विकास की गति बनाए रखने के लिये यह जरूरी है कि हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। विदेशों को निर्यात करने की दिशा में पिछले वर्ष बहुत सन्तोषजनक प्रगति हुई। औद्योगिक उत्पादन की गति में हाल की वृद्धि

के बावजूद, आयात बराबर गिरता रहा और इस तरह प्रतिस्थापन—आयात में सफलता देखने को मिली। लेकिन, चालू वर्ष के पहले सात महीनों में, बाह्य और आंतरिक कई कारणों से निर्यात उतना अच्छा नहीं हो सका। इसलिए, मेरी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने का एक ठोस कार्यक्रम हाथ में लिया है।

हमारे शोध संतुलन में अच्छी साम्यावस्था लाने के लिये अदृश्य खाते में हुई आय का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिशा में इस वर्ष कुछ प्रगति हुई है। यह सन्तोषजनक बात है कि 1968 के मुकाबले 1969 में पर्यटक अधिक संख्या में भारत आए। इसका परिणाम यह हुआ कि इस खाते में हमारी विदेशी मुद्रा की आय 27 करोड़ रुपये से बढ़ कर लगभग 32 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार हमारे जहाजों के टन-भार में वृद्धि होने से समुद्रपार का व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा अधिक मात्रा में होने लगा और अब जहाजरानी में भारतीय जहाजों का हिस्सा 18 और 20 प्रतिशत के बीच है।

हमारे देशवासियों के रहन-सहन के स्तर की वृद्धि का सम्बन्ध परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकास से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं। पिछले चार वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा है। परन्तु यदि दस वर्षों में ही आज के जन्म दर को 39 प्रति हजार से 25 प्रति हजार तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना है तो अभी इसके लिये बहुत कुछ करना बाकी है।

हमारी आर्थिक नीति के तथ्यों की परिधि यह होनी चाहिए कि रोजगार के लिये धन-सम्पदा का उत्पादन अधिक किया जाये और उसका समुचित वितरण हो और साथ ही आय-उत्पादक साधन भी बढ़ाए जायें। ये प्राथमिकतायें चौथी योजना के प्रलेख में दी जायेंगी जो कि जल्दी ही अंतिम रूप से तैयार हो

जायेगा और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मेरी सरकार को मालुम है कि बेरोजगारी हमारी अर्थ-व्यवस्था के सम्मुख ऐसी गम्भीर समस्या है जिसे जल्दी ही हल करना होगा। पिछले दो बरसों में संगठित क्षेत्र में, रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत अवरुद्ध रहने के बाद उसमें दो प्रतिशत वृद्धि हुई है; यह आगे के लिये आशाजनक है।

केन्द्र और राज्य, दोनों की योजनाओं में, पब्लिक सेक्टर के व्यय में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट रूप से वृद्धि इसलिये की गई है कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही ऐसे कदम भी उठाने हैं कि विकास के साथ-साथ रोजगार भी बढ़े। अधिक रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस दिशा में कुछ कदम पहले ही उठा लिये गये हैं। चालू वर्ष में, यह प्रबन्ध किया गया है कि राज्य सरकारें बड़े और छोटे सिंचाई कार्यक्रमों तथा गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिये अधिक धनराशि नियत करें जिससे कि बड़ी संख्या में इंजीनियरों और तकनीशनों को रोजगार मिल सके। भूमि का कृष्यकरण, छोटे सिंचाई कार्यों के नवीकरण, गांवों को मंडियों के साथ मिलाने के लिये सड़क-निर्माण के कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों से ग्राम विकास और रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

योजना के अन्तर्गत सुलभ साधनों को इकट्ठा करके गांवों में बड़े पैमाने पर एक निर्माण कार्यक्रम बनाया जायेगा जिसे 12 से 18 महीनों की अवधि में ही कार्यान्वित किया जायेगा। यह एक ऐसा काम है जिसके लिये पर्याप्त रूप से विस्तृत योजना तैयार करनी होगी और राज्य स्तर पर स्थानीय रूप से पहल करनी होगी। निर्माण-कार्य से इंजीनियरों, तकनीशनों, कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार मिल सकता है। इसलिये, मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि जिन बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर मकानों की विकट समस्या है,

वहां मकानों के लिये जमीनें देने, कम आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने और गन्दी वस्तियों की सफाई करने के लिये बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण और विकास जैसे कार्यक्रमों को पूरा करने के अधिकाधिक साधन जुटाए जायें।

हमारे तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को भी इस प्रकार का नया रुख देना होगा कि जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। हमारे पोलिटेकनीकों में अब जो शिक्षा दी जाती है, उसे उद्योगों के व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ना होगा। इसके लिये पोलिटेकनीकों में दी जाने वाली शिक्षा में परिवर्तन करना होगा ताकि सिद्धान्त को व्यवहार के साथ संबद्ध किया जा सके और प्रशिक्षण को उद्योग-कार्य से। इसके साथ ही साथ, हमें अन्य विद्यार्थियों को भी अधिकाधिक अवसर देने हैं जिससे कि वे काम का अनुभव प्राप्त कर सकें। डिग्री स्तर पर पहले दो वर्षों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम आरम्भ करने का इरादा है जो कि धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों पर लागू कर दिया जायेगा। आशा है कि इस योजना में लगभग एक लाख विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को समाज-सेवा में लगे रहने का अवसर मिलेगा जिससे वे अनुभव करेंगे कि वे भी राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार हैं।

पूंजी लगाने से अधिक रोजगार मिलेगा पर पूंजी लगाने के लिये अधिक बचत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। उनकी अधिक शाखाएं खोलने का जो साहसपूर्ण कार्यक्रम है, उससे यह आशा की जा सकती है कि पहले की अपेक्षा अब और बड़े पैमाने पर धन जमा होगा। इसके साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों को पायेदार और उत्पादक योजनाओं के लिये बैंकों से पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीयकरण की नीति में निहित भावना का प्रभाव बैंकों के कार्य-कलापों पर पड़ने लगा है और उन्होंने खेती-बाड़ी, सेवा-उद्योग और खुदरा न्यापार को उत्पादक

और लाभकारी कार्यों के लिये सहायता देना आरंभ कर दिया है जिनकी अभी तक घोर उपेक्षा की जाती रही है। उच्चतम न्यायालय के हाल में दिये गये निर्णय के आधार पर जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कानून फिर से बन जायेगा, तब जो लाभकारी प्रक्रिया अभी तक अपनाई गई है, वह और भी सक्रिय हो जावेगी।

इस स्थिति में मैं सरकार की श्रम नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस नीति का हमेशा ही यह उद्देश्य रहा है कि मजदूरों के रहन-सहन और उनके काम करने की दशा में सुधार किया जाये, उनकी मजदूरी और वेतन को बढ़ाया जाये और किसी हद तक उन्हे काम मिलने का आश्वासन भी प्राप्त हो। इस नीति के अनुसार, सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि पत्तन एवं गोदी मजदूरी बोर्डों की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये। सरकार ने लोहा तथा इस्पात उद्योग में मजदूरी के ढांचे में संशोधन करने के लिये द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है। इस आयोग ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने और प्रभावकारी सामूहिक मोल-तोल को बढ़ावा देने के लिये कई सिफारिशें की हैं। मेरी सरकार खास तौर से संगठित श्रमिकों के सभी वर्गों से अपील करती है कि वे उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सरकार के प्रयासों में सहयोग दें। अनुशासन एवं निरंतर कठिन परिश्रम के बिना देश अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता।

लेकिन सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में किये जाने वाले ये सारे प्रयास तब ही सफल हो सकेंगे जबकि शांति और सामंजस्य का वातावरण और लोकतंत्र के सिद्धांतों में अटूट निष्ठा बनी रहे। इसलिये, हिंसा की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति बड़ी चिन्ता का कारण बन गई है। यह समस्या राजनीतिक मतभेदों से परे है और सरकार इसके निराकरण के

लिये सभी राजनीतिक दलों और जिम्मेदार नागरिकों का सहयोग चाहती है।

हिंसा का सब से अधिक चिन्ताजनक स्वरूप वह है जब अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच झगड़ा होता है क्योंकि उससे सभ्य जीवन के सभी मूल्यों का विनाश होता है। 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद् की मीटिंग के बाद से माध्प्रदायिक सम्बन्धों में सुधार दिखाई दिया था। लेकिन फिर अहमदाबाद में दिल को दहला देने वाली घटनाएं हुईं। उससे हमारी प्रतिष्ठा भंग हुई और हमारे गौरव को कलंक लगा। ऐसी घटनाएं हम सब लोगों के लिये चिन्ता की हैं जो धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की मर्यादा और मानव-जीवन के प्रति आदर रखने में विश्वास करते हैं। हमें इस बात की खास तौर से बहुत चिन्ता है कि उग्रवादी राजनीतिक दल निरन्तर हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकलापों के पीछे एक राजनीतिक विचार-धारा है, जिससे वे अपने विध्वंसकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सामाजिक असन्तोष का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हम सामाजिक असन्तोष के वास्तविक कारणों को दूर करने के लिये उत्सुक हैं, लेकिन हिंसात्मक कार्रवाइयों का सख्ती से दमन करना होगा।

भूतपूर्व राज्यों के नरेशों ने हमारे इतिहास के एक संकटमय समय में जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुए एक लोकतंत्रीय शासन के अन्तर्गत भारत के शांतिपूर्ण एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी देश-भक्ति का परिचय दिया था। मुझे पूर्ण आशा है कि देश के व्यापक हित में वे उसी तरह वर्तमान युग की सामाजिक आवश्यकताओं को समझेंगे और एक बार फिर सद्भाव और सहयोग की भावना दिखायेंगे। राजाओं के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों का हमारे आज के सामाजिक उद्देश्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है और वह समतावादी सामाजिक व्यवस्था से भी मेल नहीं खाते। इसलिये, सरकार ने भारत की पूर्वी रियासतों के राजाओं के प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का

फैसला कर लिया है और इस पर अमल करने के लिये कानून लाया जायेगा। लेकिन हमारा यह विचार है कि संक्रमणकाल में कुछ ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिससे कि पूर्व नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने का समय मिल सके।

मेरी सरकार को पूरी आशा है कि चंडीगढ़ और फ़ाज़िल्का तहसील के कुछ भाग के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये गये हैं, उनसे दोनों पड़ोसी राज्यों के लोग आगे आने वाले रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगा सकेंगे। जब भावनायें भड़का दी जाती हैं, तब हर एक को सन्तुष्ट करने वाला कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं होता। लेकिन सरकार को विश्वास है कि जो निर्णय लिये गये हैं, वे न्यायसंगत और निष्पक्ष हैं। सरकार जल्दी ही एक कमीशन विधायिणी जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को फिर से ठीक करने के दावों पर विचार करेगा। भाखड़ा प्रायोजना के प्रबन्ध तथा व्यास प्रायोजना के निर्माण से सम्बन्धित वर्तमान प्रबन्धों में आवश्यक हेर-फेर करने पर भी सरकार विचार करेगी।

हमारी अगली दस वर्षीय जनगणना 1971 के आरम्भ में की जायेगी। इसके साथ हमारे देश की जनगणना के इतिहास के सौ वर्ष पूरे होंगे। भारत में जनगणना विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है और इस प्रकार के पेचीदा और बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सफलता तब ही सम्भव है जबकि केन्द्र और राज्यों की सरकारें, स्थानीय प्राधिकारीगण और प्रत्येक नागरिक इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।

विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमने अन्य देशों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने और उसे अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। शान्ति, अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और परस्पर लाभकारी सहयोग के रास्ते पर हम निरन्तर चल रहे हैं।

शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त की स्वीकृति का क्षेत्र बढ़ रहा है। शान्तिपूर्ण

सह-अस्तित्व का क्षेत्र स्थायी रूप से व्यापक हो जायेगा और इससे मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, ऐसा हमारा विचार है। हमारा विश्वास है कि सैनिक गुटों का कठोर रख डीला पड़ने और शक्ति गुटों के बीच तनाव कम होने से गुटों से अलग रहने के सिद्धान्त को अब अधिक स्वीकृति मिलने लगी है और राष्ट्रों की स्वतंत्रता, समृद्धि और स्थिरता को समृद्ध करने के अवसर बढ़ रहे हैं।

यह सन्तोष की बात है कि अपने पड़ोसी देशों—श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, अफ़गानिस्तान और ईरान—के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। उन देशों और अन्य देशों के साथ भी आपसी सहयोग और समझ-बूझ के नये रास्ते बराबर खोजे जा रहे हैं।

सरकार की यह नीति रही है कि सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाये। विकसित देशों के साथ आमतौर से और एशिया के देशों के साथ खासतौर से इस प्रकार के सम्बन्ध बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। अब जब कि भारत में कृषि और उद्योग का विकास महत्वपूर्ण अवस्था में पहुँच गया है, हमारे लिये यह सम्भव हो गया है कि हम इस दिशा में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कुछ योगदान के सके। हमने इस बात का समर्थन किया है कि एशिया एवं दूर-पूर्व के देशों की आर्थिक परिषद् (ईकाफे) के अधीन एशियाई आर्थिक सहयोग मंत्री परिषद् के जरिये व्यापक आधार पर प्रादेशिक प्रबन्ध किये जायें।

सरकार सच्चे दिल से यह चाहती है कि पाकिस्तान की सरकार और जनता के साथ समझ-बूझ, सहयोग और मित्रता बढ़े। हमने वर्तमान गतिरोध को तोड़ने के लिये पाकिस्तान सरकार को कई रचनात्मक मुझाव और प्रस्ताव भेजे। खेद है कि हमने जो पहलकदमियाँ कीं, उनका पाकिस्तान से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। फिर भी, मेरी सरकार सहयोग

की भावना, मित्रता और अच्छे पड़ोसियों के से व्यवहार के आधार पर पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की निरन्तर कोशिश करती रहेगी।

चीन के साथ भी हमारा उद्देश्य यह रहा है कि हम एक-दूसरे देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखण्डता के परस्पर आदर और एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों के आधार पर अपने सम्बन्धों का संचालन करें। हम आशा करते हैं कि चीन हमें अपनी विदेश नीति बरतने और अपने घरेलू मामलों का संचालन करने के हमारे अधिकार का आदर करेगा।

मेरी सरकार इस बात से चिन्तित है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में लड़ाई का कोई समाधान नहीं हो सका है। इन दोनों लड़ाइयों के कारण विश्व की शांति और स्थिरता पर बुरा असर पड़ा है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक विस्फोटक स्थिति में पहुँच रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा परिषद् के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव पर अमल कराये। वियतनाम में लड़ाई अभी चल रही है। मेरी सरकार ने बराबर यह कहा है कि वहाँ से तमाम विदेशी फौजों को हटाया जाये ताकि वियतनाम के लोग किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भविष्य का स्वयं ही निर्णय कर लें।

हमें बहुत-से देशों और सरकारों के प्रमुखों का अपने बीच स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष में, मैं अपने पड़ोसी मित्र देश, श्रीलंका की यात्रा पर गया था और प्रधान मंत्री ने बर्मा, अफ़गानिस्तान, जापान और इन्डोनेशिया की यात्रा की थी। ये यात्राएँ इन देशों के साथ समझ-बूझ और मित्रता बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुईं।

हम शांति के लिये कटिबद्ध हैं लेकिन हमें ऊँचे स्तर पर अपनी रक्षा की तैयारियाँ रखने के प्रति भी जागरूक रहना है। हमारी रक्षा सेनाओं को सज्जत करने में आत्म-निर्भरता की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। रक्षा-कार्यों

के लिये देश में आत्म-निर्भर औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। बहुत तरह के महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूद के विषय में हम अब आत्म-निर्भर हो गये हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोनाटिक्स और जंगी जहाजों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी देश में उत्पादन करने में काफी प्रगति की है।

अगले वित्तीय वर्ष (1970-71) के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च का व्यौरा आपके विचार के लिये जल्दी ही रखा जायेगा।

चौदह बैंकों को फिर से राष्ट्रीयकरण करने का हाल में जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसके स्थान पर सरकार संसद् के सामने एक बिल प्रस्तुत करेगी। एक बिल राज्य सभा के सामने पहले से ही है जो कि अनिवार्य वस्तु (संशोधन) अवस्थिति अध्यादेश, 1969 के स्थान पर आ जायेगा। हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 के स्थान पर भी एक बिल रखने का सरकार का इरादा है। सरकार इस सत्र में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है :—

1. प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का बिल।
2. राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अनादर रोक बिल, 1970।
3. विदेशी सहायता (नियमन) बिल, 1970।
4. फसल बीमा बिल, 1970।
5. समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना के लिये बिल।
6. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये बिल।
7. एन० सी० डी० सी० (संशोधन) बिल, 1970।
8. भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिये एक स्वायत्त-

शासी संविधिक निगम स्थापित करने के लिये बिल ।

संसद् सदस्यगण ! आप ऐसे समय में यहां इकट्ठा हो रहे हैं जबकि लोग बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। आप उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का सही मूल्यांकन करें और अपनी विवेकशीलता का बुद्धिमत्ता से उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें।

#### PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 OF THE CONSTITUTION

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY) : Sir, I beg to lay on the Table, under clause (3) of article 356 of the Constitution, a copy of the Proclamation (G.S.R. No. 236) issued by the President on February 16, 1970, revoking the Proclamation issued on July 4, 1969, under the said article, in relation to the State of Bihar (in English and Hindi). [Placed in Library. See No. LT-2516/70].

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan) : Sir, before you proceed I object to the laying of these papers before the matter is clarified.

356 के अन्तर्गत जो उद्घोषणा यहां रख रहे हैं क्या आप इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उस उद्घोषणा के साथ बिहार के गवर्नर के द्वारा भेजी गई दो रिपोर्ट्स सभा के पटल पर रखी जायं। अगर वे दोनों पत्र नहीं हैं तो क्या आप होम मिनिस्टर को इस बात के लिए निर्देश देंगे कि जो दोनों पत्र गवर्नर ने राष्ट्रपति शासन को चलाने के लिए और जल्दी समाप्त करने के लिए भेजे वे भी सदन की पटल पर रखे जायेंगे ?

MR. CHAIRMAN : I overrule this point of order. Under article 356 clause (3) it is only the Proclamation which has to be laid on the Table. No other document need to be laid on the Table.

SHRI SUNDAR SINGH BHANDARI : But there are two letters on the basis of which this Proclamation has been issued. I beseech you; they should also be laid on the Table of the House.

MR. CHAIRMAN : I cannot ask the Government to do something which is not required by the Constitution.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। 16 फरवरी का यह आदेश है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सदन में इस पर बहस होगी या नहीं ?

श्री सभापति : यह मौका नहीं है।

श्री राजनारायण : आप हर समय खड़े हो जायं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है।

श्री सभापति : आज फारमल बिजनेस का काम है।

श्री राजनारायण : तो आज इसको नहीं रखना चाहिए था।

श्री सभापति : आप एक मिनट बैठ जायं।

श्री राजनारायण : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय हमारे देश में सामान्य स्थिति नहीं हो रही है और असामान्य ढंग में राज्य सरकारें गिराई जा रही हैं और प्रधान मंत्री की इच्छित सरकारें बिठाई जा रही हैं।

MR. CHAIRMAN : This is out of order.

श्री राजनारायण : इस पर बहस होने के पूर्व मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि बिहार में 16 तारीख को...

MR. CHAIRMAN : This is out of order. Mr. Rajnarain, please sit down.

SHRI AWADSHWAR PRASAD SINHA (Bihar) : May I request you to expunge what he had said ?

श्री राजनारायण : मूझ को पूरा अधिकार है यह जानने का कि इस पर बहस कब होगी।

श्री सभापति : मैं इसको अभी नहीं बतला सकता। इसे मैं बाद में बतलाऊंगा।

श्री राजनारायण : इस पर बहस होने के पहले आप से मेरी प्रार्थना है कि आप इन पर सोमवार के लिए बहस होना निश्चित कीजिए। हम संविधान का उल्लंघन नहीं होने देंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में संविधान का उल्लंघन किया गया है।